



हर घर नल से जल के दावे फेल

पानी की टंकी परिसर बना भैंसों का तबेला



नवभारत न्यूज

श्योपुर, 23 नवम्बर। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'जल जीवन मिशन' (नल-जल योजना) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। ताजा मामला श्योपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सुमरेरा का है, जहां करोड़ों की लागत से संचालित होने वाली नल-जल योजना धरातल पर उतरने से पहले ही दम तोड़ती दिख रही है। यहां पानी की टंकी का निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन ग्रामीणों के घरों तक पानी पहुंचने के बजाय टंकी परिसर निजी भैंसों का तबेला

ग्राम पंचायत सुमरेरा में योजना शुरू होने से पहले ही खुली पोल

और चारा (करब) रखने का गोदाम बन चुका है।

कागजों में विकास, जमीन पर अव्यवस्था का आलम : ग्राम पंचायत सुमरेरा में ग्रामीणों को पेयजल संकट से निजात दिलाने के उद्देश्य से नल-जल योजना स्वीकृत की गई थी। निर्माण एजेंसी द्वारा गांव में ओवरहेड पानी की टंकी खड़ी कर दी गई, जिससे ग्रामीणों को उम्मीद जगी थी कि अब उन्हें पीने के पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन निर्माण कार्य के बाद से योजना अधर में लटकी हुई है।

वर्तमान स्थिति यह है कि पशुओं का डेरा जिस टंकी से गांव की प्यास बुझनी थी, उसके चारों ओर और परिसर में ग्रामीणों द्वारा निजी भैंसें बांधी जा रही हैं। चारे का भंडारण - टंकी के नीचे और परिसर की खाली जगह में पशुओं के लिए 'करब' (चारा) और अन्य घरेलू सामान जमा कर दिया गया है।

स्वच्छता और सुरक्षा पर सवाल - पेयजल परियोजना जैसे संवेदनशील और स्वच्छ स्थान पर मवेशियों के बंधे होने और गोबर-गंदगी फैलने से भविष्य में जल जनित बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है।

जिम्मेदार बेखबर, ग्रामीण पानी को परेशान : नल-जल योजना का कार्य अभी तक पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतर पाने के कारण सुमरेरा के ग्रामीण आज भी हैंडपंप और निजी स्रोतों के भरोसे पानी भरने को मजबूर हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि टंकी बने काफी समय बीत चुका है, लेकिन न तो नियमित जलापूर्ति शुरू हो पाई है और न ही टंकी परिसर की सुरक्षा के लिए कोई बाउंड्रीवॉल या चौकीदार की व्यवस्था की गई है। देखरेख के अभाव में दबंग और स्थानीय लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर इसे निजी तबेले में तब्दील कर दिया है।

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और कलेक्टर से मांग की है कि ग्राम पंचायत सुमरेरा की नल-जल योजना के अधूरे पड़े कार्यों को तत्काल पूर्ण कराया जाए, टंकी परिसर से अवैध कब्जा और मवेशियों को हटवाया जाए, तथा जल्द से जल्द हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

जिले की अन्य पंचायतों की तरह ही सुमरेरा में भी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और ग्राम पंचायत की लापरवाही साफउजागर हो रही है। बड़ा सवाल यह है कि जब योजना अभी तक पूरी तरह चालू ही नहीं हुई है, तो सरकारी परिसर में निजी कब्जा और पशुओं को बांधने की अनुमति किसने दी। विभागीय अधिकारी दफ्तरों में बैठकर योजनाओं की समीक्षा तो करते हैं, लेकिन मैदानी स्तर पर निरीक्षण न होने के कारण शासकीय निर्माण कार्यों की दुर्दशा हो रही है।

बाल विवाह के प्रति समुदाय को जागरूक करें : सीईओ



नवभारत न्यूज

श्योपुर, 23 नवम्बर। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री जायसवाल ने महिला बाल विकास विभाग एवं जिला शिक्षा केन्द्र डीपीसी को निर्देश दिये कि पेयजल उपलब्धता की दृष्टि से सभी स्कूलों एवं आंगनबाडियों का

पेयजल उपलब्धता की दृष्टि से स्कूल-आंगनबाड़ियों का सर्वे कराने के भी दिए निर्देश

सर्वे कराया जायें तथा इसकी सूची पीएचई कार्यालय को उपलब्ध कराई जाये। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में शादी विवाह के समय को देखते हुए बाल विवाह के प्रति समुदाय को जागरूक किया जायें।

बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्री शाक्य, एसडीएम श्योपुर सुश्री मेघा तिवारी, डिप्टी कलेक्टर श्री श्रीवास्तव आदि अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा एसडीएम विजयपुर श्री मिश्रा वर्चुअली माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

सीईओ जिला पंचायत श्री जायसवाल ने निर्देश दिये कि बायोमैट्रिक अपडेशन के लिए स्कूलों में आधार शिविर लगाये जायें, इसके साथ ही उन्होंने शत प्रतिशत विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने भ्रमण के दौरान विद्यालयों का अवलोकन कर मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण नियमित रूप से जारी रखें। सीईओ जिला पंचायत श्री जायसवाल द्वारा बैठक के दौरान निर्माण कार्यो की समीक्षा करते हुए सडक निर्माण के कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिये। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री अनिल पटेल ने जानकारी दी कि बछेरी से मालीपुरा तथा प्रेमसर से बिलवाडा रोड का कार्य पूर्ण हो गया है, सरजूपुरा से मालीपुरा सडक निर्माण की टेण्डर प्रक्रिया जारी है। सीईओ जिला पंचायत द्वारा विजयपुर-बांगरोद से भैसाई तक सडक निर्माण कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

इसके साथ ही सीएमएचओ डॉ दिलीप सिकरवार को सेसईपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया के निर्देश प्रदान किये। इस अवसर पर सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत निर्माणाधीन बालिका शौचालयों तथा स्कूलों की मरम्मत एवं अन्य निर्माण कार्यो की भी समीक्षा की गई।

सीजेएम की मौजूदगी में लगा मोबाइल कोर्ट, 28 वाहनों के कटे चालान



नवभारत न्यूज

श्योपुर, 23 नवम्बर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शहर में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के उद्देश्य से न्यायालय एवं यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) संध्या मरावी की प्रत्यक्ष उपस्थिति में सड़क पर ही मोबाइल कोर्ट लगाकर स्कूली व अन्य यात्री वाहनों की सघन जांच की गई। नियम तोड़ने वाले कुल 28 वाहनों के विरुद्ध मौके पर ही चालानी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपये का समन शुल्क (जुर्माना) वसूला गया।

इन मानकों की हुई सघन जांच

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन : स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े आवश्यक उपकरण जैसे फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर), स्पीड गवर्नर और सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता व कार्यशीलता परखी गई। दस्तावेज और वर्दी - वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ-साथ चालकों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस और निर्धारित वर्दी की जांच की गई।

ओवरलोडिंग पर नजर : क्षमता से अधिक बच्चों और सवारियों को बैठाकर चलने वाले वाहनों पर विशेष निगरानी रखी गई।

सीजेएम की सख्त हिदायत : जांच के दौरान जो स्कूली वाहन सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे या अन्य वाहन यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, उनके खिलाफमोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मोबाइल कोर्ट द्वारा तत्काल जुर्माने की कार्रवाई की गई। इस अवसर पर सीजेएम ने सभी स्कूल संचालकों और वाहन चालकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि नौनिहालों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

चार थानों की संयुक्त टीम ने संभाला मोर्चा

अभियान के दौरान सीजेएम संध्या मरावी के साथ यातायात पुलिस, कोतवाली, देहात थाना और महिला पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रही। टीम ने शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरने वाली स्कूल बसों, मैजिक वैन, ऑटो रिक्शा सहित अन्य यात्री व निजी वाहनों को रोककर बारीकी से जांच की।

वन विभाग की टीम पर किया था हमला ले गए थे ट्रैक्टर, गिरफ्तार





नवभारत न्यूज

श्योपुर, 23 नवम्बर। थाना कोतवाली श्योपुर पुलिस ने रेत माफियाओं और वन विभाग की गश्ती टीम पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस अधीक्षक श्री रहमान के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से वाहन भी जब्त किए गए हैं।

पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, 19 नवंबर 2026 को वनरक्षक रामलखन गुर्जर की रिपोर्ट पर आरोपियों वीरेन्द्र रावत (निवासी किन्नपुरा), लवकुश रावत (निवासी मोरेका), महेश रावत (निवासी अर्रौंदरी), रूपसिंह राजोरिया और राजेन्द्र रावत (निवासी श्योपुर) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि आरोपियों ने एक राय होकर रास्ते में मोटरसाइकिल खड़ी कर रास्ता रोका, वन विभाग की गश्ती टीम के साथ गाली-गलौज व डंडों से मारपीट की, ट्रैक्टर अपने साथ ले जाकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई तथा जान से मारने की धमकी दी।

इस घटना में वनरक्षक रामलखन गुर्जर, गेम रेंजर ऑफिसर (सबलगढ़) सोमेश शर्मा और वनरक्षक महेश बघेल घायल हुए थे। कोतवाली श्योपुर में अपराध क्रमांक 405/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं (191(2), 126(2), 132, 296(बी), 115(2), 351(3)) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्योपुर श्री रहमान ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया और एसडीओपी आनंद कुमार राय के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सत्यम सिंह गुर्जर के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए की कार्रवाई : 20 नवंबर 2026 - मुखबिर की सूचना पर आरोपी रूपसिंह (उम्र 34 वर्ष, पुत्र स्व. रमेश जाटव, निवासी ग्राम हीरापुरा, थाना रघुनाथपुर) को सलापुरा नहर (ग्राम कलारना) से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद - थाना परिसर कोतवाली से आरोपी लवकुश रावत उर्फ गोया (उम्र 22 वर्ष, पुत्र अनिल रावत, निवासी ग्राम मोरेका, थाना ओछापुरा) और वीरेन्द्र रावत (उम्र 23 वर्ष, पुत्र रामदयाल रावत, निवासी ग्राम किन्नपुरा, थाना ढोढर) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

21 नवंबर 2026 - मुखबिर की सूचना पर आरोपी महेश (उम्र 36 वर्ष, पुत्र धारासिंह रावत, निवासी अर्रौंदरी, थाना ढोढर) और राजेन्द्र रावत (उम्र 27 वर्ष, पुत्र रामदयाल रावत, निवासी किन्नपुरा, थाना ढोढर) को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद मेमोरेंडम लेख किया गया।

इसके बाद आरोपी महेश रावत को न्यायालय में पेश कर जेआर पर तथा राजेन्द्र रावत को पीआर पर पेश किया गया।

टीम की सराहनीय भूमिका

इस कार्रवाई में निरीक्षक सत्यम सिंह गुर्जर, उप निरीक्षक महावीर कंसाना, उप निरीक्षक सुरेश धाकड़, सहायक उप निरीक्षक रामनरेश कंसाना, आरक्षक 78 आनंद यादव, आरक्षक 500 कमलकिशोर गुर्जर और आरक्षक 298 राजकुमार माहौर की सराहनीय भूमिका रही। फिलहाल प्रकरण की विवेचना जारी है।

प्रकरणों का तुरंत करें निराकरण अन्यथा होगी कार्यवाही : कलेक्टर

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 23 नवम्बर। कलेक्टर सुश्री दाहिमा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों के

सीएम हेल्पलाइन सहित नामांतरण, बटवारा प्रकरणों की समीक्षा

निराकरण में गति लाई जायें, अगली समीक्षा बैठक के पूर्व तक सुधार नही हुआ तो संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन सहित नामांतरण, बटवारा एवं सीमाकंन के प्रकरणों की समीक्षा की गई।



बैठक के दौरान संयुक्त कलेक्टर श्री शाक्य, एसडीएम श्योपुर सुश्री मेघा तिवारी, कराहल श्री शाक्य, डिप्टी कलेक्टर श्री श्रीवास्तव सहित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद रहे। इसके अलावा एसडीएम विजयपुर श्री मिश्रा वर्चुअली माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

कलेक्टर सुश्री दाहिमा ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि राजस्व अधिकारी निर्धारित दिनो में राजस्व न्यायालयों में बैठकर मामलों का निराकरण करें। अविवादित नामांतरण प्रकरणों की समीक्षा में निराकरण का प्रतिशत 81.38 पाया गया, इसी प्रकार अविवादित बटवारा के प्रकरणों का प्रतिशत 83.58 रहा है। सीमांकन के प्रकरणों में निराकरण का प्रतिशत 97.43 है। उन्होने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अविवादित नामांतरण प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने तहसील श्योपुर, विजयपुर, बडौदा सहित राजस्व वृत्त पहेला एवं गोरस में नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण शीघ्रता से करने के निर्देश दिये।

उन्होंने निर्देश दिये कि सभी एसडीएम प्रति सप्ताह राजस्व प्रकरणों तथा सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करेंगे। उन्होंने राजस्व विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाइन के निराकरण की गति बढाये जाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि अपर कलेक्टर सहित संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर द्वारा अनुभाग वार राजस्व प्रकरणों के निराकरण की नियमित रूप से समीक्षा की जायेगी। बैठक के दौरान स्वामित्व योजना, फार्मर रजिस्ट्री, राजस्व वसूली तथा भूमि आवंटन, पीएम किसान सम्मान निधि आदि की बिन्दुवार समीक्षा की गई।

सीएमओ के अभाव में सफाई व्यवस्था ठप

नवभारत न्यूज

विजयपुर, 23 नवम्बर। नगर परिषद विजयपुर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) की अनुपस्थिति के चलते सफाई व्यवस्था प्रभावित होने का आरोप लग रहा है। नगर की नालियां चोक होने से गंदा पानी सड़कों पर

गांधी चौक से मीट मार्केट बस स्टैंड तक सड़क पर जलभराव

बह रहा है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

गांधी चौक से मीट मार्केट बस स्टैंड तक मुख्य सड़क पर नालियों का पानी बह रहा है। सड़क से गुजरने वाले वाहनों के कारण



सड़कों पर बह रहा नालियों का पानी

पानी उछलकर राहगीरों के कपड़ों पर पड़ रहा है, जिससे लोगों को असुविधा हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिए जाने से समस्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जिम्मेदारों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा।

समस्या को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। नगर परिषद में सीएमओ की व्यवस्था नहीं होने और सफाई व्यवस्था बिगड़ने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों ने नगर परिषद से नालियों की सफाई कराकर सड़क पर बह रहे पानी की समस्या का जल्द निराकरण कराने की मांग की है।

तीन ग्रामों में पराली प्रबंधन एवं ई-केवायसी शिविर आज

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 23 नवम्बर। ग्रामीणों की आधार कार्ड, समग्र आईडी एवं ई-केवायसी संबंधी समस्याओं के निराकरण तथा किसानों को पराली प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 24 नवंबर को जिले के छह ग्रामों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

यह शिविर श्योपुर विकासखंड के ग्राम भिलवाडिया, कंवरसली एवं रायपुरा में प्रात: 11 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों में ग्रामवासियों के आधार कार्ड, समग्र आईडी एवं ई-केवायसी अपडेट करने के साथ जाति प्रमाण पत्र बनाने तथा फार्मर रजिस्ट्री का कार्य भी किया जाएगा। इसके लिए शिविर प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों की दस्तावेज संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, जिससे तकनीकी त्रुटियों के कारण शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। इसी प्रकार शिविरों के दौरान किसानों को फसल अवशेष एवं पराली जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देकर उन्हें पराली का उचित प्रबंधन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कृषि विस्तार अधिकारियों के साथ उद्यानिकी, पशुपालन विभाग एवं अन्य मैदानी अमले द्वारा किसानों को पराली प्रबंधन में उपयोगी कृषि यंत्रों, कृषि अनुदान पोर्टल के माध्यम से यंत्रों की खरीदी पर शासन द्वारा दिए जाने वाले अनुदान तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी भी प्रदान की जाएगी।

विजयपुर की सड़कों पर मौत बनकर घूम रहे आवारा सांड

एक साल में 10 से अधिक मौतों और 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने का दावा, फिर भी कुंभकर्णी नींद में नगर परिषद

नवभारत न्यूज

विजयपुर, 23 नवम्बर। विजयपुर की सड़कों पर अब सफर करना भी किसी खतरे से खाली नहीं है। यहां वाहन चालकों और राहगीरों को सड़क पर गड्ढों से ज्यादा डर आवारा सांडों से लगने लगा है। नगर की गलियों, मुख्य मार्गों और बाजारों में बेखौफ घूम रहे आवारा सांड कब किस पर हमला कर दें, इसका कोई भरोसा नहीं। हालात इतने चिंताजनक बताए जा रहे हैं कि स्थानीय नागरिकों के अनुसार पिछले एक वर्ष में सांडों के हमलों से 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

हालांकि इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन नागरिकों में व्याप्त भय और आक्रोश प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विजयपुर की जनता कब तक सांडों के आतंक के साये में जीने को मजबूर रहेगी? सुबह काम पर निकलने वाला मजदूर हो, बाजार जाने वाली महिला हो, स्कूल जाने वाला बच्चा हो या बुजुर्ग—हर किसी की जान पर खतरा मंडरा रहा है। सड़कों पर घूमते भारी-भरकम सांड अचानक राहगीरों पर हमला कर देते हैं। कई लोग गंभीर चोटों का शिकार हो चुके हैं। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा। नगरवासियों में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि आम जनता की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार इतने बेपरवाह क्यों हैं? लोगों का कहना है कि यदि किसी बड़े नेता, जनप्रतिनिधि या अधिकारी को इन आवारा सांडों के हमले का सामना करना पड़ता, तो शायद अब तक पूरा प्रशासनिक अमला सड़कों पर उतरकर अभियान चला चुका होता। लेकिन गरीब, मजदूर और आम नागरिकों की जान जा रही है, फिर भी कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जनता का सवाल बेहद सीधा है—क्या आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी केवल हादसे के बाद संवेदना व्यक्त करने तक सीमित रह गई है? आखिर नागरिकों को सुरक्षित सड़कें उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है?

लोगों ने की प्रशासन से मांग

नगरवासियों ने नगर परिषद, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि तत्काल विशेष अभियान चलाकर आवारा सांडों को पकड़ा जाए और उन्हें सुरक्षित गौशाला में पहुंचाया जाए। संवेदनशील स्थानों पर नियमित निगरानी हो, पशुओं के मालिकों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था बनाई जाए। अब प्रशासन को यह समझना होगा कि आवारा सांडों का आतंक कोई छोटी-मोटी नगर समस्या नहीं, बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी से जुड़ा गंभीर सुरक्षा संकट है।विजयपुर की जनता का सवाल आज भी गूंज रहा है—आखिर कितनी और जानें जाने के बाद नगर परिषद की नींद खुलेगी? क्या किसी और परिवार के घर का चिराग बुझने के बाद ही जिम्मेदारों की आंखें खुलेंगी? जनता को खोखले वादे नहीं, सड़कों पर सुरक्षा चाहिए। अब देखना यह है कि प्रशासन कार्रवाई करता है या फिर विजयपुर की जनता यूं ही मौत के साये में जीने को मजबूर रहती है।

यदि नहीं, तो आखिर कब तक कागजों और आश्वासनों में ही व्यवस्था चलती रहेगी? विजयपुर से जनप्रतिनिधि मंत्री और विधायक जैसे महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचे हैं। इसके बावजूद नगर की बुनियादी समस्याएं आज भी आम जनता के लिए मुसीबत बनी हुई हैं।

विकास के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जब नागरिक अपनी ही सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं, तो विकास की तस्वीर अधूरी ही मानी जाएगी।चुनाव के समय जनता के बीच पहुंचकर बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद आवारा पशुओं जैसी गंभीर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई देती? जनता अब भाषण नहीं, परिणाम चाहती है। उसे आश्वासन नहीं, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए।